



आईपीएल सीजन 2026 का आगाज... 7 फिर निकला महिला आरक्षण का... 3 भाजपा के लोग ही करवा रहे... 2

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

बीजेपी की कांटो भरी राह

- » नहीं हो पा रहा जुगाड़, मोदी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़
- » युद्ध की थकान, महंगाई की मार और विदेश नीति पर उठते सवाल
- » फिलहाल बीजेपी के लिए स्थिति जटिल
- » मोदी के सामने सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि हालात भी खड़े हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। किसी भी युद्ध के बाद जो माहौल बनता है उसमें आमतौर पर सरकार को फायदा मिलता है। राष्ट्रवाद का उबाल, सुरक्षा का सवाल और मजबूत नेतृत्व की छवि। लेकिन इस बार कहानी इतनी सीधी नहीं है। क्योंकि युद्ध के साथ-साथ जो चीजे देश में जबर्दस्ती घुस आयी हैं वह हैं पेट्रोल और गैस की किल्लत महंगाई की मार और आम आदमी की जेब पर सीधा हमला। अब सवाल यही है कि पांच राज्यों में होने जा रहे चुनाव पर इन चीजों का कितना असर होगा।

सरकार किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल चुनाव में फतह हासिल करना चाहती है और बाकी की जगह अपनी जीत का मोमेंटम बरकरार रखना भी एक चुनौती है। देश एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ युद्ध का तनाव दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में घुसती महंगाई और इसी बीच चुनावों का बिगुल। इसे अगर कोढ़ में खाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं जहां जनता राहत चाहती है लेकिन सियासत उसे फिर से रणभूमि में खींच लाई है। अब सवाल यह है कि क्या जनता सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देगी या फिर अपनी रसोई में जलते चूल्हे को भी देखेगी?

क्या बीजेपी के लिए जीत आसान होगी?

अगर हालात सामान्य होते तो शायद जवाब हां में आ सकता था लेकिन इस बार कहानी सीधी नहीं है बल्कि उलझी हुई परतदार और खतरनाक तरीके से अनिश्चित है। कामज पर देखें तो

बीजेपी के पास सब कुछ है मजबूत संगठन, असीम संसाधन, और सबसे बड़ा चेहरा नरेन्द्र मोदी लेकिन जनता पर तस्वीर उतनी आसान नहीं दिखती। सबसे पहली चुनौती है क्षेत्रीय किलों की मजबूती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं हैं। वह एक

राजनीतिक भावना बन चुकी हैं। उनका दिल्ली बनाम बंगाल वाला नैरेटिव बीजेपी की हर रणनीति को स्थानीय बनाम बाहरी की बहस में बदल देता है। ममता का अंदाज टकराव का है और यही टकराव उनके समर्थकों को और ज्यादा एकजुट करता है।

क्या इसबार मोदी फैक्टर काम करेगा

बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह चुनाव को लोकल से उतकर नेशनल बना देती है। लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध की आर्थिक थकान जैसे मुद्दे सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। मतदाता अब सिर्फ नेतृत्व नहीं बल्कि नतीजे भी देख रहा है। यानी यह चुनाव सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि हालात बनाम हुकूमत का मुकाबला बनता जा रहा है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि केंद्र बनाम राज्य का टकराव। एक तरफ पीएम नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय छवि दूसरी तरफ ममता और स्टालिन जैसे क्षेत्रीय दिग्गज। ममता बनर्जी खुद को संघर्ष की प्रतीक के रूप में पेश कर रही हैं जो दिल्ली की ताकत से लड़ रही हैं। उनका हर बयान हर आरोप इसी नैरेटिव को मजबूत करता है। स्टालिन भी तमिल पहचान और क्षेत्रीय स्वभिमान के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों नेताओं की खासियत यह है कि वे अपने राज्यों में सिर्फ नेता नहीं बल्कि भावना बन चुके हैं। और चुनाव में भावना अक्सर गणित पर भारी पड़ जाती है।

05

राज्यों में होने जा रहे चुनाव पर इन चीजों का कितना असर होगा।

देश के भीतर आर्थिक बैचेनी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने यह शायद सबसे जटिल चुनौती चुनौती है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि जहां इजरायल से नजदीकी और फिर इरान की नाराजगी जैसे मुद्दे हैं दूसरी तरफ देश के भीतर बढ़ती आर्थिक बैचेनी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी सवाल उठ रहे हैं। इजरायल के साथ गले मिलाना और उसके बाद पश्चिम एशिया में संतुलन बिगड़ना क्या इसका असर भारत के ऊर्जा हितों पर पड़ेगा? क्या यही वजह है कि तेल और गैस की आपूर्ति पर दबाव दिख रहा है? जनता इन सवालों का जवाब चाहती है और चुनाव वही मंच है जहां जवाब मांगे जाएंगे। और यही से यह चुनाव सामान्य नहीं बल्कि पीएम मोदी के लिए अग्निपरीक्षा बन जाता है।

जनता को राहत की जगह मिल रही है मुश्किलें

युद्ध होते हैं खत्म होते हैं, फिर होते लेकिन युद्ध का असर लंबे समय तक दुनिया के साथ चलता है। भारत में भी यही देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में उछाल सप्लाई चेन पर दबाव और बाजार में अनिश्चितता। इन सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां जनता राहत की उम्मीद कर रही थी लेकिन उसे और मुश्किलें मिल रही हैं। तेल की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती। यह हर चीज को प्रभावित करती है। सब्जी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक। जब गैस का सिलेंडर महंगा होता है तो उसका असर सीधे घर की रसोई पर पड़ता है। युद्ध के बाद सरकार पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह स्थिति को स्थिर करे। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है क्या सरकार उस मोर्चे पर सफल रही है?

चुनावी गणित पर भारी पड़ते मौजूदा हालात

यह चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है। यह उस सवाल का जवाब है क्या राष्ट्रीय नेतृत्व स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ेगा? मोदी के सामने चुनौती साफ है उन्हें न सिर्फ अपनी छवि बचानी है बल्कि उस आर्थिक और सामाजिक असंतोष को भी खोलना है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे नेता इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध की थकान महंगाई की मार और विदेश नीति पर उठते सवाल ये सब मिलकर बीजेपी के लिए स्थिति को जटिल बना रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। एक सही नैरेटिव एक बड़ा फैसला और खेल बदल सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह चुनाव आसान नहीं है इस बार मोदी के सामने सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि हालात भी खड़े हैं।

विदेश नीति ने खोया संतुलन

विपक्ष यही नैरेटिव बना रहा है कि सरकार ने विदेश नीति में संतुलन खो दिया जिसका असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से यह संकट आया है। लेकिन चुनाव में ग्लोबल फैक्टर नहीं बल्कि लोकल दर्द काम करता है। और यही दर्द अब वोट में बदल सकता है।

बीजेपी के लिए हर राज्य में हालात चुनौतीपूर्ण हैं

एम्के स्टालिन ने अपनी छवि एक स्थिर प्रशासनिक और मजबूत नेता के रूप में बनाई है। द्रविड़ राजनीति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बीजेपी के लिए वहां जगह बनाना सिर्फ चुनावी रणनीति से संभव

नहीं यह एक लंबी वैचारिक लड़ाई है। केरल में मुकाबला पारंपरिक है लेफ्ट बनाम कांग्रेस। बीजेपी यहां लगातार कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी वह तीसरे खिलाड़ी की भूमिका से बाहर नहीं निकल पाई है। वोट शेयर बढ़ा है लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अभी भी लंबा

और कठिन है। असम में जरूर बीजेपी मजबूत दिखती है लेकिन यहां भी तस्वीर पूरी तरह सुस्थित नहीं है। स्थानीय मुद्दे पहचान, नागरिकता, और क्षेत्रीय असंतोष। कभी भी चुनावी गणित को पलट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति अक्सर आदिवासी वर्ग में अपर्याप्त मोड़ लेती है।



भाजपा के लोग ही करवा रहे जमाखोरी : अखिलेश यादव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गैस व पेट्रोल की किल्लत को लेकर भाजपा पर करारा हमला किया है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर को लेकर स्थितियां खराब हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के डिप्टी सीएम के बयान से यह साबित हो गया है कि सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम का दावा है कि जिसके यहां सिलेंडर न हो, वो हमारे यहां सूचना भेज दे, हम सिलेंडर भिजवा देंगे। डिप्टी अपना फोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल दें या अपने घर, कार्यालय या फिर सीधे अपने जमाखोरीवाले अंडरग्राउंड गोदाम का पता ही दे दें। अखिलेश ने कहा कि डिप्टी सीएम स्टूल लगाकर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों के आगे क्यों



भाजपा के लोगों ने वोट कटवाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करवाए

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोगों ने वोट कटवाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके फार्म-7 भरवाए। चुनाव आयोग का काम वोट बढ़वाना है, वोट कटवाना नहीं। हमने पीडीए के तहत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी, सबको जोड़ा है। उत्तर प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा।

नहीं बैठ जाते।

सरकार बनने पर हम नियमों से परे जाकर किसी उद्योगपति को सपोर्ट नहीं करेंगे: उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने डिजिटल

डिवाइड खत्म किया था। हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए कैबिनेट के फैसले से ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का निर्णय लिया। सरकार बनने पर हम नियमों से परे जाकर किसी उद्योगपति

बोले सपा प्रमुख- डीजल, पेट्रोल और गैस सिलिंडर को लेकर देश के हालात खराब

सपा का कथ्यप-निषाद जाति में जनाधार बढ़ाने की तैयारी

सपा ने पूर्व सांसद फूलन देवी की बड़ी बहन रुविमणी देवी निषाद को समाजवादी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। दिव्यापुर के गांव बुढ़दान में उनकी ससुराल है। रुविमणी देवी के जरिये सपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में कथ्यप-निषाद मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास किया है। रुविमणी देवी निषाद की पहचान चरित दस्यु सुंदरी और बाद में सांसद रही फूलन देवी की बड़ी बहन के रूप में रही है जिससे उन्हें जातीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर जनाधार बनाने में मदद मिली। बता दें कि फूलन देवी भी सपा के टिकट पर सांसद बनी थीं और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। रुविमणी सपा के लिए चुनावों में काम करती रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनापुरी से सांसद ड्रिपल यादव के लिए वह काम कर चुकी हैं। अब उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

को सपोर्ट नहीं करेंगे।

सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा संविधान से नहीं, मनविधान से चलती है। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है।

पीएम मोदी ने देश को अधर में छोड़ा : मसूद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण फैसलों में देरी की आलोचना की है। मसूद ने चेतावनी दी कि देश को अलग-थलग छोड़ दिया गया है और इसके गंभीर परिणाम सभी नागरिकों को प्रभावित करेंगे। स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री देर से जाग रहे हैं।



जहाँ समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए थे और जहाँ हम तटस्थ रुख अपना रहे थे, वहाँ हमें अधर में छोड़ दिया गया है। हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। स्थिति बेहद गंभीर है। लोग चिंतित हैं। व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं। लोग बहुत परेशान हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने और डीजल पर इसे हटाने के बाद यह आलोचना सामने आई है। इसके अतिरिक्त, डीजल निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) लगाया गया है। सरकार की यह कार्रवाई पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता, विशेष रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के जवाब में है।

आइए, महागठबंधन के साथ फिर बनाइए सरकार : आईपी गुप्ता

जमुई के विधायक ने सीएम नीतीश कुमार से की अपील
बयान के बाद बिहार में मचा सियासी घमासान
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जमुई। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच सहरसा से आईआईपी विधायक आईपी गुप्ता ने बड़ा और आक्रामक बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। जमुई में बातचीत के दौरान उन्होंने जदयू को खुला ऑफर देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो महागठबंधन बिना किसी शर्त के उनका समर्थन करने को तैयार है।

आईपी गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा, नीतीश कुमार जी, उधर क्यों देख रहे हैं? इधर आइए, हमलोग हैं। अगर वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। वंशवाद के मुद्दे पर भी आईपी गुप्ता ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह



केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि हर नेता पहले एक पिता होता है और अपने बच्चों को राजनीति में लाना गलत नहीं है। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण देते हुए कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने वाले खुद वही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 56 इंच के सीने और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जबकि देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। अंत में उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में आईआईपी अपनी पहली वर्षगांठ मनाएंगी, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता

सीएम नीतीश कुमार को किनारे करने की रची गई है साजिश

भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने सोची-समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का माहौल बनाया। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता पहले खुद कहते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और अब उसी आधार पर उन्हें किनारे करने की साजिश रची गई है। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर नीतीश कुमार आज यह कह दें कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होगा। नीतीश कब क्या फैसला ले लें, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम तैयार हैं।

शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

सोनिया गांधी की हालत में तेजी से हो रहा है सुधार

एक-दो दिन में मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

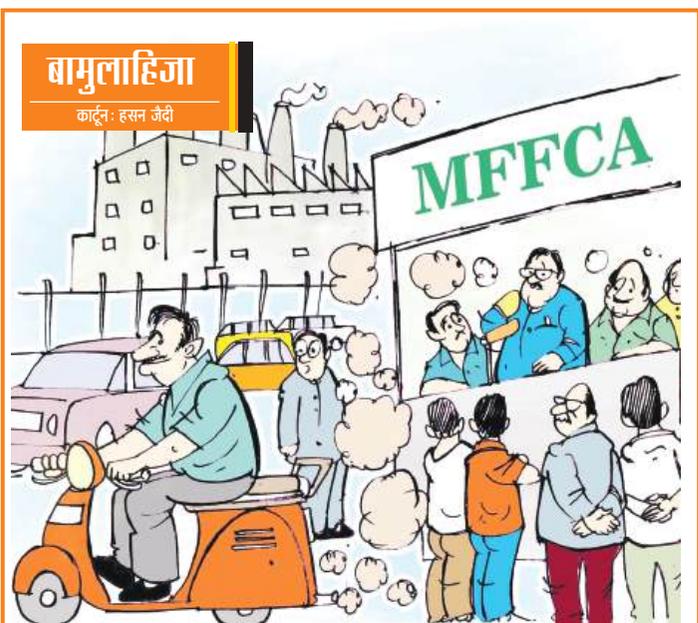
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें एक से दो दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।

सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि 79 वर्षीय नेता, जिन्हें 24 मार्च की देर रात भर्ती कराया गया था, की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। स्वरूप ने कहा कि सोनिया गांधी की हालत में काफी सुधार है। उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और वे सहज महसूस कर रही हैं। वे चल-फिर रही हैं और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है। कुल मिलाकर, उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक-दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल ने इससे पहले बताया था कि गांधी जी को एक गंभीर संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं और उन पर सकारात्मक



असर पड़ रहा है। अस्पताल ने गुरुवार को बताया कि सोनिया गांधी को बुखार के कारण 24 मार्च की रात सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में उन्हें एक गंभीर संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं और उन पर इलाज का अच्छा असर पड़ रहा है। गांधी को पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पिछले साल जून में, पेट संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया था। उसी महीने की शुरुआत में, 7 जून को, उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था।



मप्र में बिजली दर बढ़ोत्तरी पर छिड़ा संग्राम

पीसीसी चीफ का कड़ा विरोध, समाधान नहीं हुआ तो करेंगे भूख हड़ताल : जीतू पटवारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। कांग्रेस मप्र के चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा की मोहन सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली यह बढ़ोत्तरी आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनसेवा के बजाय सरकारी वसूली के मॉडल पर काम कर रही है, जबकि पहले से ही महंगाई से लोग परेशान हैं।

पत्र में यह भी कहा गया कि पिछले एक दशक में प्रदेश में बिजली दरें 22 से 24 तक बढ़ चुकी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0-50 यूनिट की दर में भी 20प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा हर



महीने (फ्यूल सरचार्ज) के नाम पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता

की जेब पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सरकार से सीधे सवाल किया बिजली कंपनियों के घाटे को जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? हर साल घाटा दिखाकर जनता से वसूली क्यों? क्या गलत प्रबंधन और भ्रष्टाचार का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है? क्या गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सिर्फ बिल भरने के लिए रह गया है? पत्र में सरकार द्वारा ईवी चार्जिंग पर दी जा रही 20प्रतिशत छूट को भी भ्रम बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में ईवी उपयोगकर्ताओं की संख्या सीमित है, ऐसे में इस छूट का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता, जबकि बिजली दरों में वृद्धि का असर हर घर पर पड़ता है।

फिर निकला महिला आरक्षण का जिन्न

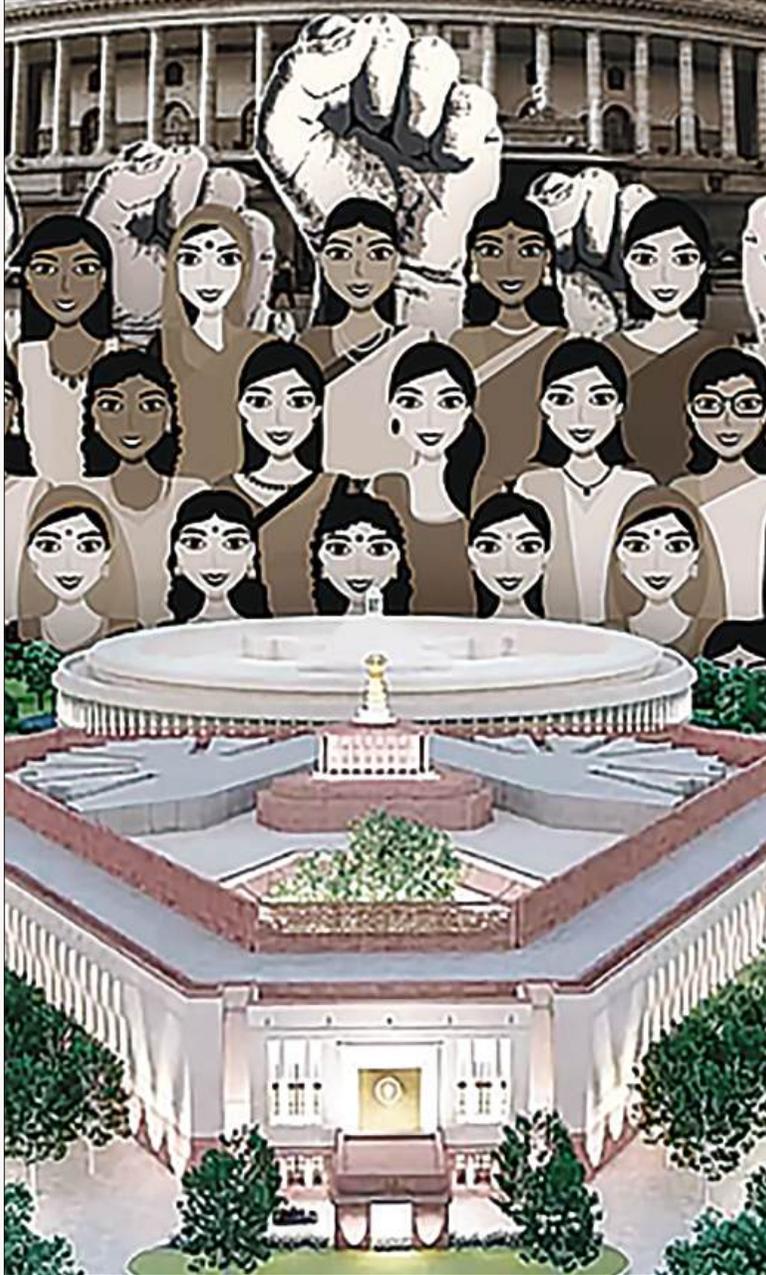
विपक्ष ने भाजपा व मोदी सरकार पर उठाए सवाल

- » सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में
- » कांग्रेस बोली- चुनावी लाभ के लिए बदल रहे नियम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एकबार फिर महिला आरक्षण का जिन्न बोलत से बाहर निकल आया है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठा लिए हैं। मोदी सरकार महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जो मौजूदा विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की आचार संहिता अब मोदी आचार संहिता बन गई है। कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि सरकार महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अगले पखवाड़े में संसद का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

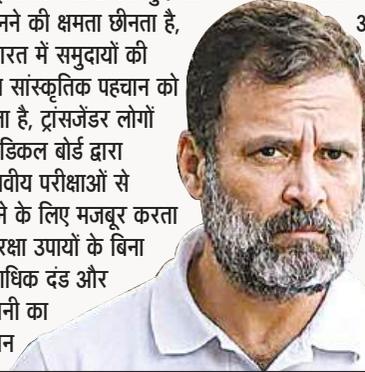
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को "मोदी आचार संहिता" में बदल दिया है। अगले महीने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सितंबर 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित करके किया गया था, जिसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण भी प्रदान किया गया। परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये दोनों आरक्षण लागू होने थे।" उन्होंने कहा कि जब नारी वंदन विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही थी, तब कांग्रेस ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने की मांग की थी। रमेश के अनुसार, उस समय मोदी सरकार ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि परिसीमन और जनगणना दोनों को पहले पूरा करना होगा।



ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक समुदाय को करेगा कलंकित

राहुल गांधी ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकारों एवं पहचान पर सीधा हमला है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। ट्रांसजेंडर समुदायों के कुछ लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भाजपा सरकार का ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकारों और पहचान पर एक खुला हमला है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रतिगामी विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए, ट्रांसजेंडर लोगों की खुद को पहचानने की क्षमता छीनता है, पूरे भारत में समुदायों की विविध सांस्कृतिक पहचान को मिटाता है, ट्रांसजेंडर लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा अमानवीय परीक्षाओं से गुजरने के लिए मजबूर करता है, सुरक्षा उपायों के बिना आपराधिक दंड और निगरानी का प्रावधान

करता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस समुदाय से परामर्श नहीं किया और एक विधेयक लाया गया जो उनकी रक्षा करने के बजाय उन्हें 'कलंकित' करता है। राहुल गांधी ने कहा, "संविधान प्रत्येक भारतीय के जीवन, स्वतंत्रता, पहचान और सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है। यह भाजपा सरकार हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है और अपने संकीर्ण विचारों के चलते ट्रांसजेंडर समुदायों को सम्मान देने के भारत के समृद्ध इतिहास को नष्ट कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का स्पष्ट रूप से विरोध करती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बीते 13 मार्च को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिदेना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके।



सरकार अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के प्रभाव में काम कर रही

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर बढ़ते वैश्विक संकट के बीच भारत की विदेश नीति से समझौता करने का आरोप लगाया। गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की कूटनीतिक स्थिति अब स्वतंत्र नहीं रही और सरकार अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के प्रभाव में काम कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सरकार से पूछा- सर्वदलीय बैठक कब बुलाएंगे

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर सरकार से नारी वंदन अधिनियम, 2023 में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। अपने पत्र में खरगे ने कहा कि सरकार सितंबर 2023 में पारित संविधान संशोधन में एक और संशोधन करने की योजना बना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि

सभी विपक्षी दल प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार-विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपनी मांग को दोहराएंगे। खरगे ने सुझाव दिया कि बैठक को सार्थक बनाने के लिए सरकार को प्रस्तावों का विस्तृत विवरण देते हुए एक नोट



जारी करना चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि यह बैठक विधानसभा चुनावों के वर्तमान दौर के 29 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने के बाद आयोजित की जाए। उच्च सूत्रों के अनुसार, सरकार ने दो बड़े संशोधन करने की योजना बनाई है। 2023 के नारी शक्ति वंदन

अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था। जनगणना में देरी के कारण, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने की योजना है। परिसीमन और सीटों के पुनर्वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। संशोधन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं।

कांग्रेस को दिल्ली के अकबर रोड और रायसीना रोड दफ्तर खाली करने के नोटिस पर बवाल

केंद्र सरकार ने कांग्रेस को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने दो प्रमुख कार्यालयों—24 अकबर रोड (राष्ट्रीय मुख्यालय) और 5 रायसीना रोड—को खाली करने का बेदखली नोटिस दिया है। नोटिस के अनुसार, पार्टी को ये दोनों संपत्तियां 28 मार्च तक खाली करनी होंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पृष्ठि की है कि नोटिस कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुए थे, जिससे पार्टी के पास कानूनी और राजनीतिक बचाव के लिए बहुत कम समय बचा है। पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड और एक और अहम जगह 5 रायसीना रोड के लिए बेदखली के नोटिस

दिए गए हैं, और खाली करने की आखिरी तारीख 28 मार्च तय की गई है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने इस बात की पृष्ठि की कि नोटिस कुछ दिन पहले मिले थे, जिससे पार्टी के पास जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचा है। पार्टी अब अपने अगले कदमों पर विचार कर रही है, जिसमें अदालत जाना और सरकार से और समय मांगना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस संपत्ति के आवंटन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए थोड़े और समय का अनुरोध कर सकती है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह है कि किसी सीनियर नेता को राज्यसभा में लाया

जाए और बंगला उनके नाम पर आवंटित करवाया जाए, जिससे वह लगातार इस्तेमाल के लिए योग्य हो जाए। हालांकि, इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा से पहले तेजी से राजनीतिक और कानूनी दांव-पेच चलने की जरूरत होगी। 24 अकबर रोड, जो लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व से जुड़ा रहा है, के संभावित रूप से हाथ से निकल जाने के प्रतीकात्मक और व्यावहारिक, दोनों तरह के असर होंगे। 5 रायसीना रोड के साथ-साथ, ये संपत्तियां दिल्ली में पार्टी के तालमेल और फैसले लेने के लिए अहम केंद्रों के तौर पर काम करती रही हैं।

प्रधानमंत्री की छवि खराब है

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए गांधी ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री की छवि खराब है, तो हमारी विदेश नीति भी खराब है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत का कूटनीतिक रुख मोदी की निजी विदेश नीति में बदल गया है और कहा कि हर कोई इसे एक मजाक समझता है।

पलटी मारने के उस्ताद हैं पीएम : जयराम रमेश

जयराम ने दावा किया कि अब "पलटी मारने के उस्ताद" ने 30 महीने बाद अपना मन बदल लिया है और परिसीमन एवं जनगणना की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही आरक्षण लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान भटकाने के हथियारों का



उपयोग करने में माहिर हैं। वह ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं और अब फिर वही कर रहे हैं। अपनी विदेश नीति की विफलताओं तथा देश के सामने मौजूद एलपीओ और ऊर्जा संकट से ध्यान हटाने के लिए वह इस नयी पहल के साथ आए हैं।

कोविड-19 महामारी का जिक्र करने पर आपत्ति

विपक्ष के नेता ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के संदर्भ में संसद को संबोधित करते हुए मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी का जिक्र करने पर भी आपत्ति जताई। गांधी ने कहा कि कल उन्होंने एक अप्रसंगिक भाषण दिया। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए, उनका कोई पद नहीं है। महामारी के दौरान झेली गई कठिनाइयों का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि कोविड जैसा समय आने वाला है। वे मूल गए हैं कि तब क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे और किस तरह की त्रासदी घटी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा हालात में महामारी का जिक्र करना असंवेदनशीलता और समझ की कमी दर्शाता है।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

रफ्तार पर नियंत्रण से बचेगी जान

आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग गाड़ियों को चलाते समय रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और आपस में टकराकर जान गवां रहे हैं। इस हालात से थोड़ी सी सावधानी से खतरे को टाला जा सकता है। उधर इस मौसम की वजह से शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए सरकारी स्तर पर तो प्रयास जरूरी हैं ही सामाजिक स्तर पर भी कोशिशें होनी चाहिए। कुछ उपायों जैसे कार्यस्थलों पर लचीले समय को प्रोत्साहन मिले। बैंगलूर, गुडगांव जैसे शहरों में सप्ताह में कई कंपनियों ने सप्ताह में तीन दिन तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक और किफायती बनाया जाए। मेट्रो, बस रैपिड ट्रांजिट और साइकल वाहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रिक साइकिल और पैदल मार्गों की सुरक्षा हो। सख्त पार्किंग नियम बने। अवैध अतिक्रमण हटें। सड़कों पर जाम के लिए जिम्मेदार बड़ी व लज्जरी कारों की बढ़ती संख्या है।

भारत में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना स्टेटस सिंबल समझा जाता है। जितनी बड़ी गाड़ी, उतना ही अधिक स्टेटस और अहंकार। कई बार बड़ी कारों में पांच के स्थान पर एक सवारी ही नजर आती है। यही गाड़ियां सड़कों पर जाम का बड़ा कारण है। चाहे कितनी ही सड़कें चौड़ी हो जाएं, शहरों में फ्लाइंग ओवर की संख्या बढ़ जाए लेकिन जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जाम से निजात पाना दूर की कौड़ी है। यदि ये कम हो जाएं तो सड़कें खाली खाली नजर आएंगी। उच्च अधिकारियों व नेताओं को आम जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा, सड़कों से अतिक्रमण को हटाने के लिए भी शहरी सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। बस, मेट्रो और ई-रिक्शा जैसे साधनों की संख्या और उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय उनका उपयोग करें। कारपूलिंग तथा राइड-शेयरिंग ऐप्स को प्रोत्साहन दिया जाए। फ्लाइंग ओवर, अंडरपास और रिंग रोड बढ़ाए जाएं। साथ ही स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं। अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई और मल्टी-लेवल पार्किंग की व्यवस्था हो। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वे बिना आवश्यकता वाहन न निकालें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। बसों और ट्रेनों जैसी कुशल और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए, ताकि लोग निजी वाहनों की जगह इनका उपयोग करें। सड़कों का विस्तार हो व मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाए। बढ़ते वाहनों और जाम को कई जगह चिन्हित करके वन वे जोन बनाने चाहिए। साथ ही सिग्नल्स की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

दलबदल की सियासत और जनता की खामोशी

केवल तिवारी

चाय के बागान के लिए मशहूर असम में इन दिनों सियासी उबाल जोरों पर है। चुनावी माहौल है। पार्टियों का दौर है। इधर एक ने पार्टी छोड़ी, दूसरा लपकने को तैयार। एक दल से दूसरे दल में जाने की होड़ सी मची है। इस बार पूर्वोत्तर भारत के इस अहम राज्य असम का चुनाव कई मायनों में खास होगा। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा के 'फायर ब्रांड' नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के तीखे बोल चर्चा का विषय बनते हैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई भी निजी टिप्पणियों पर उतर आए हैं। असम के जानकार कहते हैं कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन कांग्रेस से छोड़कर जाने वाले नेताओं के कारण इस पार्टी के शीर्ष नेताओं को चिंता में डाल दिया है।

तीसरी बार वापसी की कोशिश कर रही भाजपा के सामने सत्ता विरोधी लहर जैसी चुनौतियां हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के लगातार दौरों से हिमंता का हौसला बढ़ा है, इसके इतर कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राज्य का दौरा कर चुकी हैं। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए वह असम जातीय परिषद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) के साथ गठबंधन करके भाजपा का मुकाबला करने की योजना बना रही है। कांग्रेस को अल्पसंख्यक मतदाताओं, विशेषकर बांग्ला भाषी मुसलमानों का समर्थन हासिल हो सकता है, क्योंकि हिमंता अक्सर इनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। यही कारण है कि गोगोई 2024 में सत्तारूढ़ भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद जोरहाट लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। इसके विपरीत भाजपा नीत राजग में असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल

और बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने सीएम हिमंता को जलुकुबारी सीट से ही इस बार फिर उम्मीदवार बनाया है। सरमा लगातार पांच बार यहां से जीते हैं और अब छठी बार किस्मत आजमा रहे हैं।

इसके साथ ही भाजपा के मौजूदा सांसद हितेंद्र नाथ गोस्वामी को जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। असम के प्रत्याशियों के नाम दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किए। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में संबंधित बैठक हुई। यहां उल्लेखनीय

हुए असम कांग्रेस के पूर्व नेता प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा को क्रमशः दिसपुर तथा बिहपुरिया सीट से उतारा गया है। ये प्रत्याशी जिताऊ साबित होंगे या पुरानी पार्टी छोड़ने के कारण जनता उन्हें नकार देगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। इसे सियासी बिसात कहें या कुछ और कि बोरदोलोई के भाजपा में जाने से फिर टिकट पाने के बीच ही उनके बेटे प्रतीक ने घोषणा कर दी कि वह अपनी 'मूल' पार्टी कांग्रेस में तो बने रहेंगे, लेकिन मार्गरेटा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। यहां



है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। असम की सियासत में एक रोचक नजारा इस वक्त है। सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के कई चेहरे तो सामने हैं ही, भाजपा में भी अनेक चेहरे पुराने कांग्रेसियों के ही हैं। खुद मुख्यमंत्री सरमा पूर्व कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से खटपट के बीच उन्होंने पार्टी छोड़ी, भाजपा का दामन थामा और मुख्यमंत्री बन गये। अभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा और तीन अन्य विधायक सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। बोरा राज्य में बड़ा नाम है और वह बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि उसके वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो गये। उन्हें भाजपा ने टिकट भी दे दिया। भाजपा में शामिल

गौरतलब है कि खड़गे पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष भी हैं। रोचक है कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में प्रतीक को मार्गरेटा सीट से उम्मीदवार नामित किया था। यहीं से उनके पिता चार बार विधायक चुने गए थे।

खैर, मुकाबला दोनों के बीच है, लेकिन चेहरे 'कांग्रेसी' ही दिखेंगे। असम के चुनावी 'दलदल' के बीच जनता खामोश है। नेताओं की रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन यह वोटों में कितना तब्दील होगा, उसका अंदाजा अभी सियासी पंडित नहीं लगा पा रहे हैं। असम विधानसभा की 126 सीटें हैं। इनके लिए एक ही चरण में मतदान नौ अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना अन्य चार राज्यों की तरह चार मई को ही होगी। देखना होगा कि एकमात्र चरण में होने वाले कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए मशहूर पूर्वोत्तर के इस अहम राज्य में आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा।

डॉ. सुधीर कुमार

भारत में कानूनी शिक्षा को केवल एक स्नातक डिग्री हासिल करने के माध्यम के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य ऐसे सजग 'सोशल इंजीनियर' तैयार करना है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिला सकें। हाल ही में अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ (2026) मामले में उच्चतम न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। स्पष्ट किया कि कानूनी शिक्षा जैसे नीतिगत मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह वक्तव्य संकेत करता है कि वर्तमान में जारी 4 साल बनाम 5 साल की अवधि का विवाद केवल समय की गणना का नहीं, बल्कि 'गुणवत्ता, सार्थकता और परिपक्वता' का है।

कानून कोई यांत्रिक या तकनीकी विषय नहीं जिसे सिर्फ सूत्रों से समझा जा सके; यह समाज, संस्कृति व नैतिकता के ताने-बाने से बुना हुआ है। सफल 'विधिवेत्ता' बनने के लिए छात्र को वे सामाजिक मूल्य आत्मसात करने हेतु पर्याप्त 'मानसिक स्पेस' व समय चाहिये। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण देश में कानूनी शिक्षा का स्वरूप अनिवार्य रूप से न्याय की सुलभता पर केंद्रित होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का बड़ा दोष है कि यह मुख्यतया कॉर्पोरेट घरानों व उच्च न्यायालयों के लिए वकील तैयार करती है। हमें यह ढांचा बदलने की जरूरत है ताकि वकीलों को ग्रामीण और जिला स्तर की अदालतों के लिए भी समान रूप से तैयार किया जा सके। इसके लिए 'लोक अदालत' और 'मध्यस्थता' जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य और

न्याय की सुलभता हो कानूनी शिक्षा का मकसद



व्यावहारिक हिस्सा बनाना होगा। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका यहां और भी अहम हो जाती है। उन्हें स्थानीय विधिक समस्याओं, जैसे ग्रामीण भूमि विवाद, पारिवारिक उत्तराधिकार और सामुदायिक न्याय प्रणालियों पर 'क्लीनिकल रिसर्च' को बढ़ावा देना चाहिए।

जब तक कानून का छात्र जमीन से नहीं जुड़ेगा, न्याय की वास्तविक अवधारणा को नहीं समझ पाएगा। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो कानूनी शिक्षा का ढांचा इस बुनियादी प्रश्न पर टिका है कि इसे 'सामान्य स्नातक' माना जाए या 'विशेषज्ञता वाला पेशा'। भारत में 5-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम सबसे लोकप्रिय है, जो छात्र को शुरू से ही कानूनी परिवेश में ढाल देता है। इसके उलट, अमेरिका में कानून 'पोस्ट-ग्रेजुएट' शोध विषय है। पश्चिमी देशों में कानून 'अकादमिक अनुसंधान' का विषय है, जबकि भारत में इसे 'व्यावसायिक कौशल' तक सीमित कर देते हैं। विकसित देशों के संस्थान 'विधिक तर्कशीलता' के साथ ही विषयांतर अनुशासनात्मक शिक्षा पर बल दे रहे हैं। हमें भी अब कानून को डेटा साइंस, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना होगा। अंतरिक्ष कानून,

ऊर्जा कानून और खेल कानून जैसे उभरते क्षेत्रों को अपना वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने को अनिवार्य है। मौजूदा दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने विधिक शोध और दस्तावेज लेखन बेहद सरल बना दिया।

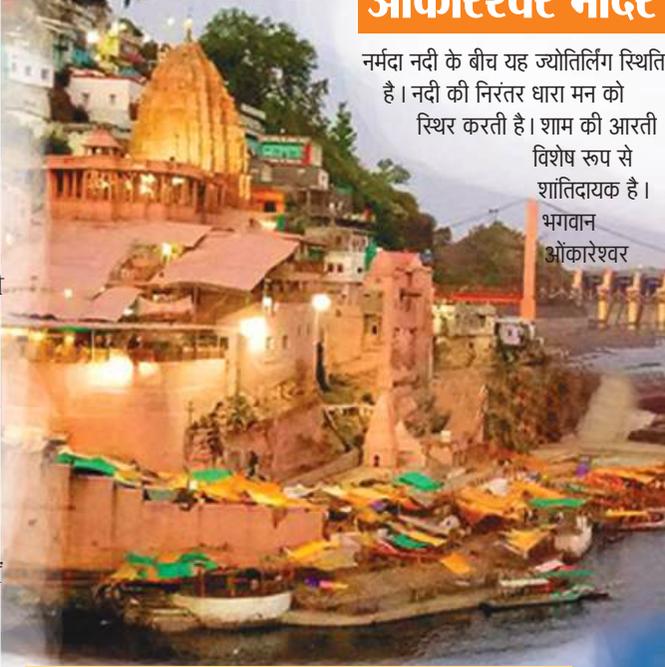
कानून से जुड़े बुनियादी कार्य मशीनों द्वारा किए जाने की प्रबल संभावना है। चुनौती 'मानवीय विवेक बनाम मशीन' की है। अधिवक्ताओं को 'मशीनी निर्भरता' पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। मशीनी एल्गोरिदम जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन उस 'मानवीय अंतर्दृष्टि' और 'व्यावसायिक नैतिकता' का स्थान नहीं ले सकते जो एक जटिल मामले में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए जरूरी होती है। इसलिए, पाठ्यक्रम में 'विधिक तकनीक', 'डिजिटल नैतिकता' और 'साइबर सुरक्षा कानून' को अनिवार्य शामिल करना चाहिए। सफल अधिवक्ता वही होगा जो तकनीक को 'गुलाम' की तरह उपयोग करे, न कि उसका गुलाम बन जाए। 'लीगल डिजाइन थिंकिंग' का उपयोग कर कानून की जटिलताओं को सरल बनाकर आम आदमी के लिए सुलभ बना सकते हैं। भारतीय कानूनी जगत की विडंबना

है कि न्याय की भाषा आज भी मुख्यतः अंग्रेजी है, जबकि बहुसंख्यक आबादी इस भाषा से अपरिचित है। 'बहुभाषी शिक्षा' और 'कानूनी अनुवाद' को बढ़ावा देना समय की मांग है। वास्तविक विधिक क्रांति तब आएगी जब एक वकील अपनी स्थानीय भाषा में जटिल कानूनों को समझा सके और न्यायालय में पैरवी कर सके। शिक्षा का माध्यम ऐसा हो जो भाषाई बाधाओं को तोड़ कानून की समझ को सर्वव्यापी बनाए। जब तक कानून की पढ़ाई बोझिल और औपनिवेशिक शब्दावली से मुक्त नहीं होगी, तब तक यह समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए 'अनुसुलझी पहली' रहेगी।

जैसे मेडिकल छात्र के लिए अस्पताल में बिताया गया समय उसके कैरियर की नींव होता है, वैसे ही लॉ छात्रों के लिए 'लीगल एड क्लीनिक्स' और 'मूट कोर्ट्स' वास्तविक पाठशालाएं हों। छात्रों को वास्तविक मुकदमों, क्लाइंट काउंसलिंग और कानूनी ड्राफ्टिंग का व्यावहारिक अनुभव मिले। पाठ्यक्रम में छात्रों के 'मानसिक स्वास्थ्य' और 'वर्क-लाइफ बैलेंस' पर भी ध्यान दिया जाए। 'एल्गोरिदम की समझ' और 'ऑनलाइन विवाद समाधान' के इस युग में सफलता का मंत्र अब केवल 'किताबी ज्ञान' नहीं, बल्कि 'तकनीकी निपुणता' और 'व्यावहारिक कौशल' का मेल है। बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोर्ड लॉ कॉलेज (2023) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मानकों में सुधार न्यायिक ढांचे के लिए अपरिहार्य है। विश्वविद्यालयों को अब 'वकीलों की फौज' पैदा करने वाली फैक्ट्री बनने से रुकना होगा। हमें ऐसे 'नीति निर्माता' और 'न्याय के प्रहरी' तैयार करने हैं जो न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों, बल्कि अपनी मिट्टी और सामाजिक समस्याओं से भी गहरे जुड़े हों।

भारत के ये हैं सबसे शांत मंदिर

कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही शोर खत्म हो जाता है और मन को शांति मिलती है। भारत के इन मंदिरों में बेचैनी और जल्दीबाजी पीछे छूट जाती है। यहां की भीड़ भी आपको परेशान नहीं करती, बल्कि दौड़भाग भरी जिंदगी में सुकून देती है। चाहे केदारनाथ की ठंडी हवा हो या तिरुवनमलै की गहरी शांति या फिर तुंगनाथ की ऊंचाई, यह सब मन को स्थिर कर देते हैं। यहां पूजा से पहले ही ध्यान शुरू हो जाता है। अगर आप भी जीवन की दौड़ में थोड़ी देर ठहरकर खुद से मिलना चाहते हैं, तो ये मंदिर मन की शांति के लिए सबसे उपयुक्त हैं।



ओंकारेश्वर मंदिर

नर्मदा नदी के बीच यह ज्योतिर्लिंग स्थिति है। नदी की निरंतर धारा मन को स्थिर करती है। शाम की आरती विशेष रूप से शांतिदायक है। भगवान ओंकारेश्वर

ओर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहां पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे के आकार वाली पहाड़ पर

विराजमान हैं। यहां भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बिना व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है।

तुंगनाथ मंदिर

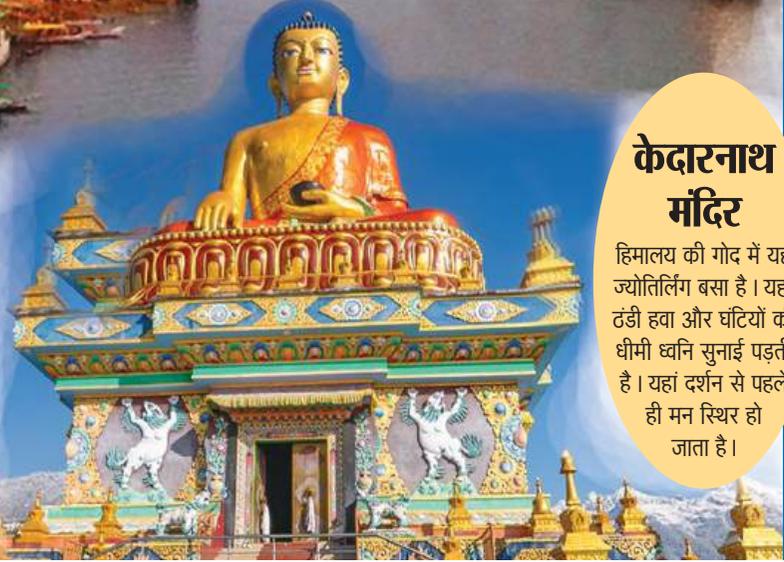
दुनिया में सबसे ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर का शिव मंदिर स्थित है। यहां कम भीड़, खुला आकाश और गहरी शांति मिलती है। ध्यान और आत्मचिंतन के लिए यह एक आदर्श स्थान है। वहीं अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और उनके सभी मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते हैं तो यहां जाकर आप शिव के दर्शन के साथ-साथ बर्फबारी का भी मजा ले सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर महादेव के पंच केदारों में से एक है। ये मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में एक बहाड़ पर बना हुआ है।

केदारनाथ मंदिर

हिमालय की गोद में यह ज्योतिर्लिंग बसा है। यहां ठंडी हवा और घंटियों की धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहां दर्शन से पहले ही मन स्थिर हो जाता है।

तवांग मठ

पहाड़ों के बीच यह बौद्ध मठ बसा है। शोर-शराबे से काफी दूर और पूरी तरह शांत जगह है। इसे ध्यान, मौन और आत्मअनुशासन का केंद्र कहते हैं। तवांग मठ से प्रकृति का मनोरम दृश्य मंत्रमुग्ध करता है। ऊंचे पहाड़ों और ठंडी बहती नदियों के बीच पर्यटकों को खूब मजा आता है। यहां पर अनेक स्थल हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के पास ले जाते हैं। दोंग घाटी पर्यटकों के लिए बेहद सुंदर उपहार है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता अविस्मरणीय है। हरे-भरे वातावरण से घिरी ग्लो झील आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा छगलोगम, वालोंग, हवा कैंप, तेजू बोटानिकल गार्डन और तेजू पार्क घूम सकते हैं।



शिरडी साई बाबा मंदिर

शिरडी साई बाबा मंदिर श्रद्धा और सबूरी का जीवंत उदाहरण है। यहां बैठकर मौन में समय बिताने का अवसर मिलता है। यह स्थान आस्था के साथ मानसिक सुकून भी देता है।



हंसना मना है

विष्णु अपने पति से- तुम सच में बहुत सीधे साधे और भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। पति- सच कह रही हो, शुरुवात तो तुम्हारे पापा ने ही की है।

पति - अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी करोगी? वाईफ - नहीं, मैं अपनी बहने के साथ पूरी जिन्दगी रह लुंगी। वाईफ - अगर मैं मर गयी तो तुम दूसरी शादी करोगे? हसबैंड- मैं भी तुम्हारी बहने के साथ पूरी जिन्दगी रह लूंगा।

पहला दोस्त- 'यार मैं जिस लड़की को चाहता हूँ, उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त- 'तुमने उसे बताया कि तेरा चाचा करोड़पति है? पहला दोस्त- 'हां मैंने बताया था। दूसरा दोस्त- 'तो फिर? पहला दोस्त-अब वो लड़की मेरी चाची है।

पति- मरते वक्त बीवी से-अलमारी से तेरा गोल्ड सेट मैंने ही चोरी किया था ! बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी, पति- तेरे भाई ने तुझे 1 लाख अमानत दी थी, वो भी मैंने गायब की ! बीवी- मैंने आपको माफ किया! पति- तेरी कमेटी के पैसे भी मैंने ही चोरी किये थे! बीवी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी मैंने ही दिया है।

कहानी श्री गणेश और देवता कुबेर

कुबेर धन और वैभव के देवता हैं। माना जाता है कि उनके पास ढेर सारा धन है और यह आपने सुना ही होगा कि जरूरत से अधिक पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। कुबेर को लगने लगा कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धन उनकी के पास है और उन्हें इस बात पर घमंड होने लगा। एक दिन अपने धन का दिखावा करने के लिए कुबेर ने महाभोज का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवतागण को बुलाया। कार्यक्रम का न्योता लेकर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास भी गए और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। भगवान शिव ने एक बार में कुबेर के घमंड को भांप लिया और फिर सोचा कि इसे सही पाठ पढ़ाना जरूरी है। यह सोचकर उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर, हमें तुम्हारा न्योता स्वीकार है, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण हम महाभोज में नहीं आ पाएंगे, किंतु तुम चिंता न करो। हमारी जगह, हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आएगा। भगवान शिव की बात सुनकर कुबेर खुशी-खुशी वहां से चले गए। महाभोज का दिन आ गया। सभी देवतागण कुबेर के घर पधारने लगे। भगवान श्री गणेश भी समय से कार्यक्रम में पहुंच गए। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, भगवान गणेश ने सारा भोजन खत्म कर दिया। जब कुबेर ने बाकी मेहमानों के लिए फिर से भोजन बनवाया, तो गणपति ने फिर से सारा भोजन खा लिया। भगवान गणेश कुबेर की रसोई में रखा सारा खाना खत्म करते जा रहे थे, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। धीरे-धीरे करके कुबेर के पास मौजूद सभी खाने की चीजें खत्म हो गईं, तो उन्होंने भगवान गणेश से कहा, प्रभु और खाना आने में समय लगेगा। तब तक आप बैठ जाइए। इस पर भगवान गणेश ने कहा, अगर तुमने मुझे अभी भोजन नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे महल में रखी हर चीज खा जाऊंगा। यह सुनते ही कुबेर घबरा गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांग ली।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

मेघ 	बिगड़े काम बनेंगे। निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। कोई पुराना रोग बाधा का कारण हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।	तुला 	आय में निश्चितता रहेगी। शत्रु शांत रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय से लाभ होगा। बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें। दौड़पुप की अधिकता का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।
वृषभ 	धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सत्य का लाभ मिलेगा। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे।	वृश्चिक 	आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी। बनते कामों में बाधा उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। काम में मन नहीं लगेगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है।
मिथुन 	वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। विशेषकर गृहनिर्माणों लापरवाही न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। दुश्जन हानि पहुंचा सकते हैं।	धनु 	जल्दबाजी व लापरवाही से हानि होगी। राजकीय कोप भुगतान पड़ सकता है। विवाद न करें। शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रसन्नता रहेगी। बिछड़े मित्र व संबंधी मिलेंगे।
कर्क 	वाणी में शब्दों का प्रयोग सोच-समझकर करें। प्रतिद्वंद्विता में कमी होगी। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी।	मकर 	कोई अनहोनी होने की आशंका रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। रोजगार मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी।
सिंह 	स्थायी संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। मनपसंद रोजगार मिलेगा। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कर्ज समय पर चुका पाएंगे। बैंक-बैलेंस बढ़ेगा।	कुम्भ 	आंखों का विशेष ध्यान रखें। चोट व रोग से बचाएं। पुराना रोग उभर सकता है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय की गति धीमी रहेगी।
कन्या 	किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्त उठा पाएंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। व्यापार में वृद्धि के योग हैं।	मीन 	यात्रा मनोनुकूल रहेगी। कारोबार से संतुष्टि रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रयास सफल रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग करें। प्रमाद न करें। निवेश से लाभ होगा।

रामनवमी पर धुरंधर 2 ने दिखाया भौकाल

धुरंधर : द रिवेंज फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने महज आठ ही दिनों में जो ताबड़तोड़ कमाई की है, वो हम देख ही रहे हैं। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी आठ दिनों के अंदर ही हजार करोड़ के पार पहुंच गया है। तो वहीं दूसरे हफ्ते ही शुरुआत भी फिल्म की काफी अच्छी हुई है। अब रिलीज के नौवें दिन यानी रामनवमी के मौके पर भी रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।



रिलीज से एक दिन पहले इस फिल्म के पेड प्रिव्यूज रखे गए थे। जिनसे फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपये की कमाई की। रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। रिलीज के चौथे दिन

फिल्म ने 114.85 करोड़ रुपये की कमाई की। रिलीज के पांचवें दिन 65.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

रिलीज के छठवें दिन 56.60 करोड़ की कमाई कर ली है। रिलीज के सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन 48.75 करोड़ रुपये रहा। तो वहीं रिलीज के आठवें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म ने रिलीज के आठ

दिनों में इंडिया में 624.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। नौवें दिन की ऑक्यूपेंसी धुरंधर 2 की रिलीज के बाद से ही फिल्म लगातार कलेक्शन के मामले में काफी रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो ये हर रोज बदलती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। फिल्म के नौवें दिन की सुबह के समय की ऑक्यूपेंसी 15.38 प्रतिशत रही है।

रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जो पाकिस्तान में भारतीय जासूस के पहुंचने और स्थापित होने की कहानी दिखाती है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ ही सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, आर माधवन नजर आए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड तोड़ रही है लेकिन दर्शकों को सिनेमा का एक अलग ही अनुभव भी दे रही है।

बॉलीवुड मन की बात

मुझे खून से लथपथ गुस्सैल रोल नहीं करना : इमरान खान



बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'धुरंधर 2' का क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है और लगातार रिकॉर्ड बना रही है। इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म की चारों तरफ हो रही प्रशंसा के बीच अब अभिनेता इमरान खान का कहना है कि उन्हें खून से लथपथ, गुस्सैल और हिंसक किरदार निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 'धुरंधर' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों की लोकप्रियता के बीच इमरान खान का ये बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है। इमरान ने रेडिट पर आस्क मी एनिथिंग सेशन में फैंस के सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक प्रशंसक ने उनसे माचो और अल्फा मैन जैसे रोल्स से बचने की अपील की। इसके जवाब में इमरान ने कहा, 'हां, मुझे खून से लथपथ, गुस्सैल और बालों वाले आदमी का किरदार निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की भूमिकाएं पहले ही काफी निभाई जा चुकी हैं।' इस दौरान एक अन्य प्रशंसक ने पूछा कि जब फिल्म इंडस्ट्री में अल्फा मैन को ही असली मर्द की परिभाषा के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे में इमरान मर्दानगी को कैसे परिभाषित करते हैं? इस पर एक्टर ने कहा कि 'फिल्मों और पूरी दुनिया में जिस तरह से मिसॉजिनी और टॉक्सिक मर्दानगी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे डर है कि पुरुष इन विषयों पर बात करने से कतराते हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें लगता है कि दूसरों के कामों के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। इसी वजह से ये यह बात भूल जाते हैं कि मर्दानगी की ये सीमित परिभाषाएं पुरुषों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। सच्ची ताकत इमोशनल भावनाओं में ही होती है।' इमरान खान ने हिंसक, एग्रेसिव और महिलाओं के खिलाफ दिखाए जाने वाले अत्यधिक वॉयलेंस पर भी चिंता जाहिर की।

धुरंधर 2 के बाद अब 'आखिरी सवाल' करेंगे संजय दत्त

संजय दत्त इन दिनों फिल्म धुरंधर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। संजय दत्त की अगली फिल्म का एलान कर दिया गया है। इसका नाम 'आखिरी सवाल' है। संजय दत्त फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। जानिए कब देख सकेंगे संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल। 'आखिरी सवाल' के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। 'आखिरी सवाल' का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। इसकी पटकथा उत्कर्ष नैथानी ने लिखी है। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की स्टार कास्ट



'आखिरी सवाल' फिल्म में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। कथित तौर

पर संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर आधारित बताई जा रही है। यह फिल्म एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के इर्द गिर्द घूमेगी।

आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बार फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे अभिनेत्रियां नजर आएंगी। इसका पहला पार्ट दर्शकों को पसंद आया था, ऐसे में ये फिल्म संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' के लिए सिनेमाघरों में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ध्रुव सरजा की बहुप्रतीक्षित एक्शन-थ्रिलर फिल्म केडी : द डेविल 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन प्रेम ने किया है।

नदी से शादी, फिर मनाई एनिवर्सरी! अजीबो-गरीब है इस अनोखी 'वॉटर लव स्टोरी' का राज

क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान बहती हुई नदी को अपना जीवनसाथी बना ले? इंग्लैंड की एक महिला ने न केवल एक नदी से विवाह किया, बल्कि अपनी शादी की तीसरी सालगिरह भी पूरे उत्साह के साथ मनाई। अब सवाल यह उठता है कि इस अनोखे प्यार के पीछे असली वजह क्या है क्या यह सिर्फ एक अजीब शौक है या इसके पीछे कोई गहरी भावना छिपी हुई है? दुनिया में आपने प्यार की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इंग्लैंड की Meg Avon की कहानी सबसे अलग और थोड़ी रहस्यमयी है। ब्रिस्टल में रहने वाली 29 वर्षीय मेग ने किसी इंसान से नहीं, बल्कि बहती हुई River Avon को अपना जीवनसाथी चुना है। हैरानी की बात यह है कि इस रिश्ते को तीन साल हो चुके हैं और मेग का कहना है कि उनका यह प्यार समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पेशे से रिसर्चर और लेखिका मेग ने जून 2023 में एक खास समारोह के दौरान इस नदी के साथ 'शादी' की थी। उनका कहना है कि वह हर हफ्ते अपनी इस 'पार्टनर' के साथ समय बिताने के लिए पानी में उतरती हैं। चाहे कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो या बर्फ जैसा ठंडा पानी, उनका लगाव उन्हें नदी तक खींच ही लाता है। जहां कुछ लोग इसे अजीब मानते हैं, वहीं मेग के लिए यह प्रकृति से जुड़ने का एक गहरा और आध्यात्मिक अनुभव है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अनोखी शादी का उद्देश्य सिर्फ सुर्खियां बटोरना नहीं है। दरअसल, Meg Avon इस रिश्ते के जरिए लोगों का ध्यान नदियों में बढ़ते प्रदूषण और सीवेज की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हैं। वे Conham Bathes नाम के समूह के साथ मिलकर नदी को 'कानूनी व्यक्ति' का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि जब तक इंसान प्रकृति को अपना नहीं समझेगा, तब तक उसकी सही मायने में रक्षा नहीं हो पाएगी। मेग की यह पहल आज के समय में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे पति-पत्नी के रिश्ते को कानूनी मान्यता मिलती है, वैसे ही नदियों को भी अधिकार मिलने चाहिए। जब पानी साफ और स्वच्छ होता है, तो उन्हें अपने इस अनोखे रिश्ते का भविष्य और उज्वल नजर आता है।



अजब-गजब इस स्नेक आइलैंड पर जाने वाले का लौटना होता है मुश्किल

इंसानी मांस पिघला देते हैं यहां के सांप, बसती है साक्षात मौत

प्रकृति जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी हो सकती है। ब्राजील के साओ पाउलो तट से करीब 33 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों-बीच एक ऐसा टापू मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। इस आइलैंड का नाम यू तो 'इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे' है, लेकिन दुनिया इसे 'स्नेक आइलैंड' के नाम से जानती है। यह एक ऐसी जगह है, जहां पैर रखते ही मौत निश्चित है। इसीलिए करीब 430000 वर्ग मीटर में फैले इस टापू पर इंसानों का जाना सख्त मना है। यहां दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लांसहेड वाइपर का साम्राज्य है। एक अनुमान के मुताबिक, इस टापू पर प्रति 75 वर्ग मीटर में कम से कम एक सांप मौजूद है, यानी आप जहां भी कदम रखेंगे, वहां एक शिकारी आपकी ताक में बैठा होगा।



स्नेक आइलैंड की लोककथाएं डरावनी कहानियों से भरी हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार एक मछुआरा केला खोजने के चक्कर में इस टापू के किनारे उतर गया था, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। एक और कहानी उस लाइटहाउस कीपर के परिवार की है, जो 1920 के दशक तक यहां रहता था; कहा जाता है कि खिड़कियों से घुसे सांपों ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इंसान को काटने की कोई रिपोर्ट दर्ज

रुकते थे। समय के साथ, इनका जहर मुख्य भूमि पर रहने वाले इनके पूर्वजों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। अगर जहर तुरंत असर न करता, तो पक्षी उ? जाते और सांप भूखे रह जाते। जब पक्षी नहीं होते, तो ये सांप छिपकली और मेंढक खाकर अपना पेट भरते हैं। वर्तमान में ब्राजील सरकार ने इस टापू पर आम लोगों के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। यहां केवल कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं और जीवविज्ञानियों को ही विशेष अनुमति के साथ जाने दिया जाता है। ब्राजील की नौसेना साल में एक बार यहां के लाइटहाउस की मरम्मत के लिए रुकती है, जो अब पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो चुका है। लेकिन खतरों के बावजूद, वन्यजीव तस्कर चोरी-छिपे इस आइलैंड पर घुसपैट करते हैं। ब्लैक मार्केट में एक 'गोल्डन लांसहेड वाइपर' की कीमत लाखों रुपये में होती है, जिसके लालच में तस्कर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। यह आइलैंड विज्ञान के नजरिए से एक चमत्कार है, जहां एक प्रजाति ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी शारीरिक संरचना और जहर को पूरी तरह बदल लिया। लेकिन आम इंसान के लिए यह केवल 'यमराज का घर' है। यहां के घने जंगलों में छिपे हजारों सुनहरे सांप इस टापू के असली मालिक हैं और वे नहीं चाहते कि कोई भी उनके इलाके में दखल दे।

दिल्ली की राजनीति में मचा बवाल !

» एलपीजी सिलेंडर को लेकर भारी हंगामा

» भाजपा व आप में तीखी बहस

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन की बैठक एलपीजी सिलेंडरों की कथित कमी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों के विरोध-प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को भारी हंगामे में कुछ ही मिनट में समाप्त हो गई। शुक्रवार को हुई इस बैठक में पार्क और सड़कों के नामकरण से संबंधित कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान आप पार्षदों ने नारेबाजी की और 'एलपीजी गायब' लिखे एलपीजी सिलेंडरों की तस्वीरों वाले पोस्टर लहराए। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पिछली बैठकों की तरह इस बार भी 'आप' के कुछ पार्षदों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया।

मेयर ने दिल्ली सरकार के बजट में एमसीडी के लिए आवंटित 11,412 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत किया। आप पार्षद एवं सदन में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा के महापौर ने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की अनुमति तक नहीं दी। नारंग ने कहा, जल्दबाजी में एजेंडा पारित कर सदन

एमसीडी सदन में भाजपा पर विपक्ष का सवाल



ग्रीन बजट सर्वसम्मति से पास होने के साथ ही विस सत्र का समापन

विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन वर्ष 2026-27 का ग्रीन बजट सर्वसम्मति से पास हो गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्रियों ने बजट पर चर्चा के दौरान इसकी खूबियां गिनाईं। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लगातार है कि आम आदमी पार्टी ने सड़क पर ही रहने का फैसला कर लिया है। दिल्ली की जनता इन्हें अगली बार स्थायी सड़क पर ही कर देगी। अतिम दिन ग्रीन बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। हालांकि बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन चर्चा के दौरान राजनीतिक माहौल काफी

गरम रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार सदन से दूर रहे, जिस पर सत्तापक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें जनता ने अपनी आवाज उठाने के लिए चुना, वे ही सदन में नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अब सड़क की राजनीति करने का फैसला कर लिया है। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी।

भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही

स्थगित कर दिया गया और महापौर परिसर से चले गए। यह केवल गैस सिलेंडर की कमी का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन से

जुड़ा बड़ा संकट है। रसोई ठंडी पड़ रही है और भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सदन में पारित प्रस्तावों में गाजीपुर स्थित पांच एकड़ भूखंड पर

कांग्रेस-भाजपा मिले हुए हैं : भगवंत मान



पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, गुजरात में पिछले 30 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने बदलने की कोशिश की लेकिन जिसको आपने विकल्प में रखा वो भी उनके साथ मिल गए। यह किसानों का क्षेत्र है, यहां पानी की समस्या है। कहा गया था कि नर्मदा नदी का पानी हर क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा लेकिन नहीं पहुंचाया गया। आज से 4 साल पहले जब हम (पंजाब में) सरकार में आए, तब 21 या 22 प्रतिशत नदियों का पानी पंजाब के खेतों में जाता था। 4 साल में हमने उसे बढ़ाकर 78 प्रतिशत कर दिया है। ये दिखाता है कि अगर नीति साफ हो तो काम हो सकता है... गुजरात में कोई विपक्ष नहीं है, कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं।

प्रतिदिन कम से कम 800 टन कचरा संसाधित करने और उससे जुड़े अवशेष के निपटान के लिए एक सुविधा विकसित करने हेतु निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

भाजपा को केरल में नहीं मिलेगी एक सीट : वेणुगोपाल

» कांग्रेस सांसद ने एलडीएफ और भाजपा के अपवित्र गठबंधन की आलोचना की

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोच्चि। कांग्रेस सांसद और एआईसीसी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने केरल में एलडीएफ और भाजपा के गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि आगामी केरल विधानसभा चुनावों में गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि कांग्रेस और यूडीएफ की जीत निश्चित है, क्योंकि केरल की जनता पिनारयी विजयन के नेतृत्व में एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन चाहती है। वेणुगोपाल ने दावा किया कि दोनों पार्टियों के बीच एक अपवित्र गठबंधन है। उन्होंने कहा कि वे सोचते हैं कि वे एक या दो-तीन सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला।



केरल विधानसभा में एक सीट जीतना उनके लिए एक सपना ही हो सकता है। वे केरल चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, भले ही वे सीपीएम और भाजपा के इस अपवित्र गठबंधन के साथ कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि केरल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके पास धन बल है, लेकिन केरल एक अलग राज्य है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी उम्मीदें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। जनता का मिजाज कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ के पक्ष में है। आप देख सकते हैं कि केरल का पूरा मिजाज बदलाव के लिए है, सरकार के बदलाव के लिए। हमें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। केरल में पिनारयी सरकार के 10 साल केरल की जनता के लिए सबसे बुरे दौर रहे हैं। लेकिन 9 अप्रैल को केरल की जनता उन्हें दिखाएगी कि केरल क्या सोच रहा है। कांग्रेस नेताओं का परिवार है। हमारे अपने विचार हैं, शायद थोड़े अलग हों। लेकिन जब भी कोई साझा मुद्दा आता है, हम सब एक साथ होते हैं। अब हर केरलवासी सरकार के बदलाव की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने की हमारी अपनी प्रणाली है। चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व केरल की जनता के साथ बैठेगा और वे फैसला करेंगे।

पीएम भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करें : उमर

मुख्यमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त कराने को कहा

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त कराने के लिए भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह किया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए, अब्दुल्ला ने क्षेत्र में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस संकट ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी पीड़ा का कारण बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संघर्ष को लेकर होने वाली चर्चाओं में अक्सर सत्ता परिवर्तन, होमरुज जलडमरूमध्य और तेल की बढ़ती कीमतों जैसे रणनीतिक और राजनीतिक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि मानवीय पीड़ा, विशेष रूप से ईरान में, पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने भारत पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को भी उजागर किया। जम्मू और कश्मीर के लोगों सहित कई भारतीय नागरिक इस समय ईरान में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इसका असर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और परिवारों में बढ़ती चिंता के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, हमें इस सदन में अपनी चिंताएं उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि विधानसभा युद्ध को रोक नहीं सकती, लेकिन भारत को मजबूत कूटनीतिक स्थिति उसे शांति की दिशा में योगदान देने की क्षमता प्रदान करती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार रचनात्मक भूमिका निभा सकती है।

हुसैनाबाद में लगा भ्रष्टाचार का दीमक

» पूरा संचालन निजी हाथों में सौंपने का खेल?
» लखनऊ विकास प्राधिकरण के नए टेंडर में करोड़ों की धांधली

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ के हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली ऐतिहासिक संपत्तियों और स्मारकों को निजी हाथों में देने या उनके प्रबंधन के निजीकरण की खबरें समय-समय पर चर्चा में रही हैं। इसबार फिर वह सुर्खियों में है। अबकी बार एक टेंडर के लिए जिस पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लखनऊ के एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा शासन को भेजी गई एक विधानिक आपत्ति ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया गया है तक हुसैनाबाद के



दो महीने में ही सब बदल गया?

ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के संचालन लिए जो नया टेंडर तनकाला गया है, उसमें ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं जो न केवल सरकारी खजाने को चूना लगा रही हैं, बल्कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए फिट की गई हैं। दो महीने के भीतर एक ही काम के लिए दो अलग-अलग टेंडर तनकाले गए। जब दोनों टेंडरों में तुलना की

48 घंटे का अल्टीमेटम

याचिकर्ता ने प्रमुख सचिव और कमिश्नर से मांग की है इस सदिग्ध टेंडर प्रक्रिया तुरंत रोक लगाई जाए। उन फाइलों की जांच हो जिन्होंने इन बदलावों को मंजूरी दी है। साथ ही वेतावनी दी गई है तक अगर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला हाई कोर्ट और जनहित याचिका जाएगा। अब देखना यह है तक शासन इस सफेद हाथी बन चुके टेंडर की जांच कराता है या हुसैनाबाद की वियसम को खामोशी से निजी स्वार्थ की गैट वढ़ा दिया जाता है।

गई तो धांधली की बू आने लगी। अमीरों के लिए रास्ता खोला-पुराने टेंडर में कंपनी का सालाना टर्नओवर 4 करोड़ था उसे नए टेंडर में बिना कोई कारण बताए 10 करोड़ कर दिया गया। वहीं काम के अनुभव की शर्तों को ढीला कर दिया गया। पहले सरकारी विभागों के लिए काम का अनुभव अनिवार्य था, लेकिन नए टेंडर में हटाकर किसी भी प्राइवेट अनुभव क मान्य कर दिया गया है। पुराने टेंडर में सरकार को 20 लाख का सालाना किराया मिलना था।

आईपीएल सीजन 2026 का आगाज आज से

» चैंपियन आरसीबी को रोकने की हैदराबाद के सामने होगी चुनौती

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का आगाज आज से होने जा रहा है, और पहले ही मुकाबले में गत चैंपियन आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच बंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी आत्मविश्वास के साथ नए सीजन की शुरुआत करना चाहेगी। इस सीजन में आरसीबी की बल्लेबाजी काफी मजबूत दिख रही है। ओपनिंग में विराट कोहली और फिल सॉल्ट उतर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिवकल अहम भूमिका निभाएंगे। फिनिशिंग की जिम्मेदारी टिम डेविड और रोमारियो शोफर्ड पर होगी।

जबकि सनराइजर्स के पास भी ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, किशन और हेनरिक क्लासेन के रूप में धाकड़ बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार और करुणाल पांड्या पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया में चोट से उबरकर पूरी तरह फिट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वह बाद में टीम में शामिल हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दयाल पूरे सत्र से बाहर रहेंगे। आरसीबी को अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, स्पिनर करुणाल पांड्या, सुयश शर्मा और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव पर काफी हद तक निर्भर रहना होगा। वहीं, पिछला सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छा नहीं रहा था और टीम अंक तालिका में छोटे स्थान पर रही थी। इस बार टीम बेहतर

बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगी पिच

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच टी20 मैचों के लिए बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। यहां की छोटी बाउंड्री और पार्लेट विकेट बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देती है। तेज गेंदबाजों को यहां काफी सख्तदारी से गेंदबाजी करना होगी, जबकि स्पिनर्स को गेंद को रोककर और टर्न दिलाकर असेट दिखाना होगा।

प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस भी शुरुआती चरण में टीम में नहीं होंगे। ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है। ओपनिंग में ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा तेज शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि लियाम लिविंगस्टोन निचले क्रम में ताकत बढ़ाएंगे।



और घातक हुई पश्चिम एशिया की लड़ाई अब पूरी दुनिया को खूब जलाएगी महंगाई

29वें दिन भी हर ओर धुंआ ही धुंआ, ईरान ने इस्राइल पर दागी मिसाइल, एक की मौत

» यमन ने भी इजरायल पर दागी मिसाइलें

» अमेरिका को उम्मीद सैन्य अभियान हफ्तों में खत्म हो जाएजा

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग को तीन हफ्तों से ज्यादा समय बीत चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन तेहरान ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इसबीच अमेरिका ने दस दिन के लिए लड़ाई रोकने की बात कही है। पर इन सब दावों के बाद इजरायल व ईरान एक दूसरे पर बम चला रहे हैं। उधर इन सबके बीच पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की रिपोर्ट आ रही हैं।

जानकारों का कहना है अब महंगाई का बम पूरे विश्व को अपने चपेट में लेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 29वें दिन भी जारी है। इन सबके बीच अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध में यमन भी कूद पड़ा है। ईरान ने इस्राइल पर दागी मिसाइल, एक की मौत हो गई है। वही यमन ने भी इजरायल पर हमला कर दिया है। यमन ने कई मिसाइलें दागी हैं। वहीं अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान महीनों नहीं, बल्कि हफ्तों में खत्म हो जाएजा और वह जमीन पर सेना तैनात किए बिना ही अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये बातें कही।

भारत को लेकर रिपोर्ट में विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि ऊंचे कच्चे तेल के दाम और कमजोर मांग मिलकर स्टेगफ्लेशन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इससे हाल के आर्थिक सुधारों पर असर पड़ सकता है और घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले महीनों में भारत की खुदरा महंगाई दर 6 से 7 प्रतिशत से ऊपर जा सकती है। अंत में रिपोर्ट ने कहा है कि मौजूदा हालात अस्थायी नहीं हैं। ऊंचे तेल के दाम, सख्त वित्तीय परिस्थितियां और बार-बार होने वाले भू-राजनीतिक झटके अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थायी विशेषताएं बन सकते हैं, जिससे लंबी अवधि तक समायोजन का दौर जारी रह सकता है।

अमेरिका के सैनिक भी भेजे जा रहे

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहा कि हालांकि इस क्षेत्र में कुछ सैनिक भेजे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विकल्प और ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर कोई आपात स्थिति पैदा हो तो वे उससे निपट सकें। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पूरे मध्य-पूर्व में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है।

अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और सैन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित है।

अमेरिका के 12 सैनिक घायल



दक्षिणी लेबनान में इस्राइली हमले में एक नर्स की मौत

दक्षिणी लेबनान के कफर तबनित इलाके में इस्राइल के हमले में एक नर्स की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह हमला

सिविल डिफेंस की एंबुलेंस को निशाना बनाकर किया गया। हमले के बाद स्थानीय अधिकारियों ने इसे गंभीर घटना बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने की मांग की

है। इस घटना को युद्ध के नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। इलाके में तनाव बना हुआ है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा



अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजार एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। सिस्टमेटिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा हालात केवल तात्कालिक उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं, जो आगे चलकर बार-बार उभर सकते हैं और लंबी अवधि तक अनिश्चितता बनाए रख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बाजार फिलहाल हर युद्ध से जुड़ी खबर पर उम्मीद और डर के बीच झूल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा बदलाव चल रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बदलती नीतियां और ईरान की प्रतिक्रिया मिलकर ऐसी स्थिति बना रही हैं, जहां निवेशकों के लिए लंबी अवधि के जोखिमों का आकलन करना मुश्किल हो गया है।

ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ड्रोन हमला

ओमान के दक्षिणी प्रांत की राजधानी सलालाह के बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें एक विदेशी कर्मचारी घायल हो गया। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, दो ड्रोन ने पोर्ट को निशाना बनाया। इस हमले में एक व्यक्ति को मध्यम चोटें आईं, जबकि बंदरगाह

पर मौजूद एक क्रेन को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा एजेंसियों ने घटना के बाद इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस घटना को गंभीर माना जा रहा है।

अबू धाबी में मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरा, पांच भारतीय घायल

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शनिवार को मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से पांच लोग घायल हो गए और दो जगह आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना खलीफा इकोनॉमिक जोन्स अबू धाबी के पास हुई, जहां सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। मीडिया ऑफिस ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोक लिया गया था, लेकिन उसके टुकड़े गिरने से नुकसान हुआ। एडी पोर्ट्स समूह के इस औद्योगिक इलाके में आग पर काबू पाने के लिए फायर टीमें तैनात की गईं। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है।